कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उपकरणों और कीटनाशियों पर केन्द्रीय सहायता की मंजूरी को सकसंगत ठहरा दिया गया है। पौध रक्षण उपकरणों तथा रसायनों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता बहुत सी केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत उपलब्ध हैं।

ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) कृषि अनुसंधान वैज्ञानिकों ने, कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत सी गैर-रासायनिक व्यवहार्य प्रौद्योगिकियां शुरू की हैं। कीट प्रबन्ध के नए प्रस्ताव, अर्थात् समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) से गैर-रासायनिक नियंत्रण उपायों के उपयोग को वरियता देने का प्रोत्साहन मिलता है। सरकार ने, राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इस कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के खेतों में कृषि विस्तार अधिकारियों तथा किसानों का व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शामिल है। 1994–95 के दौरान, समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता, बहुत सी केन्द्रीय केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध हैं।

Lack of funds for projects in farm research

7145. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "No funds for farm research projects" as reported is the Statesman dated 15th April, 1994;

(b) if so, whether the farm research projects in the country are lagging behind;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the allocations made for 1994-95 for farm research projects; and

(e) the details of the scheme formulated for extensive growth of farm research during the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The news item refers to reduction of financial support for the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, one of the 18 institutions of the Consultative Group on International Agricultural Research, promoted by the World Bank, Food and Agriculture Organisation and United Nations Development Programme. The news-item does not pertain to reduction of funds for Farm Research Projects of the Indian Council of Agricultural Research funded by the Government of India.

(d) As far as allocations for ICAR are concerned, the budget approved for 1994-95 is as under:

Plan . . .	Rs. 275.00 crores
Non-Plan . .	Rs. 202.00 crores

(e) During the VIIIth Plan period two new National Institutes, 7 National Research Centres and 5 All-India Coordinated Research Projects have been initiated thereby increasing the research activities through a network of 45 Institutes, 4 National Bureaux, 30 National Research Centres, 9 Project Directorates; and 77 All India Coordinated Research Projects.

Losses in the crop yield due to pests

7146. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any study has been undertaken at the Central level so far to ascertain State-wise losses accruing to nearly twenty to thirty per-cent of crop yields due to pests and other diseases particularly in Rajasthan and Orissa;

(b) if so, the names of such States which are most affected alongwith the damage caused to the crops during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 till date;

(c) whether any 'Action Plan' has been envisaged by the Central Government in the Eighth Five Year Plan period to combat this menace; and

(d) if so, the detajls thereof particularly in the States of Rajasthas and Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) No comprehensive studies have been made regarding the exact extent of losses to crops due to pests and other diseases in the states. However, generally the incidence of pests and diseases during last three years has been noticed in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhara Pradesh, Tamil Nadu, Karnatka, Kerala, Orissa, Assam and Mizoram.

(c) and (d) During VIII Plan, Government is implementing a comprehensive Central Sector Integrated Pest Management (IPM) Scheme. Under this Scheme, emphasis is being given on training of State Extension Workers and Farmers in the farmer's fields so that they can effectively adopt IPM approach to maximise crop production.

In the State of Orissa, 13 Districts namely; Balasore, Bolangir, Cuttack, Dhenkanal Ganjam, Kalahandi, Keonjhar, Karaput, Mayurbhanj, Phulbani, Puri, Sambalpur, Sundergarh have been identified for implementing IPM in rice during 1994-95 Similarly in Rajasthan, 4 Districts namely; Banswara, Bundj, Dungarpur, Gaganagar and one District namely; Sriganganagar have been identified for implementing IPM in rice and cotton respectively during 9994-95.

पशुओं की खाल का व्यर्थ जाना

7147. **श्री सोमपाल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मृत पशु गृह न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 18 लाख पशुओं की खालें बेकार चली जाती हैं –

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा अन्य समितियों ने देश भर में मृत पशु गृहों की स्थापना हेतु कई बार संस्तुति की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमें विदेशों से भारी मात्रा में पशुओं की खालों का आयात करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक रूप से मरने वाले करोड़ों मवेशियों तथा जानवरों की खालों का उपयोग करने के लिए ऐसे गृहों की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय-बद्ध योजना बनाई है और उस योजना के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करने के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेतराम): (क) कच्चे चमड़े और खालों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट (1986) में अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रतिशर्ष 8.9 मिलियन गोपशु और 9.3 मिलियन मेष सदृश पशुओं की खालें निकाली नहीं जाती।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं 1992–93 के दौरान 37581.85 मिलियन रुपए के